दिल्ली

वर्ष 50/अंक 01/अक्टूबर 2021

कल बनाएं बेहतर

विकास DEVELOPMENT

बदलती दिल्ली

चौतरफा विकास

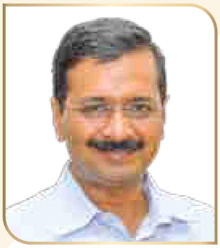

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
दिल्ली सचिवालय, आई.पी.एस्टेट,
नई दिल्ली-110002
ऑफिस - 23392020, 23392030

संदेश

दिल्ली सरकार का सूचना एवं प्रचार निदेशालय, 'दिल्ली' पत्रिका का पुनः प्रकाशन कर रहा है। ये दिल्ली के लिए बेहद हर्ष की बात है। पिछले 6 वर्षों में दिल्ली के विकास की चर्चा देश ही नहीं, दुनिया में भी हो रही है। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों और विकास सम्बन्धित योजनाओं के बारे में सही जानकारी पहुंचाने में 'दिल्ली' पत्रिका बेहद उपयोगी साबित होगी।

मैं पत्रिका के प्रकाशन पर सूचना एवं प्रचार निदेशालय और संपादकीय टीम को शुभकामनाएं देता हूं।

(अरविन्द केजरीवाल)
मुख्यमंत्री, दिल्ली

विजय देव
मुख्य सचिव,
दिल्ली सरकार

संदेश

दिल्ली सरकार समाज के हर वर्ग की उन्नति के लिए लगातार काम कर रही है। साथ ही प्रशासनिक स्तर पर योजनाओं के सशक्त कार्यान्वयन ने दिल्ली में विकास को नया आयाम दिया है। दिल्ली सरकार का सूचना एवं प्रचार निदेशालय दिल्ली पत्रिका की फिर से शुरुआत कर रहा हैं। ये हमारे लिए हर्ष का विषय हैं। दिल्ली सरकार के विकास कार्यक्रमों की सटीक जानकारी आम जनता तक पहुंचाने के लिए ये गंभीर प्रयास सराहनीय हैं। संपादकीय टीम और प्रकाशन विभाग को शुभकामनाएं।

(विजय देव)
मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार

वर्ष 50/अंक 01/अक्टूबर 2021

दिल्ली

मासिक पत्रिका

दिल्ली सरकार

आप की सरकार

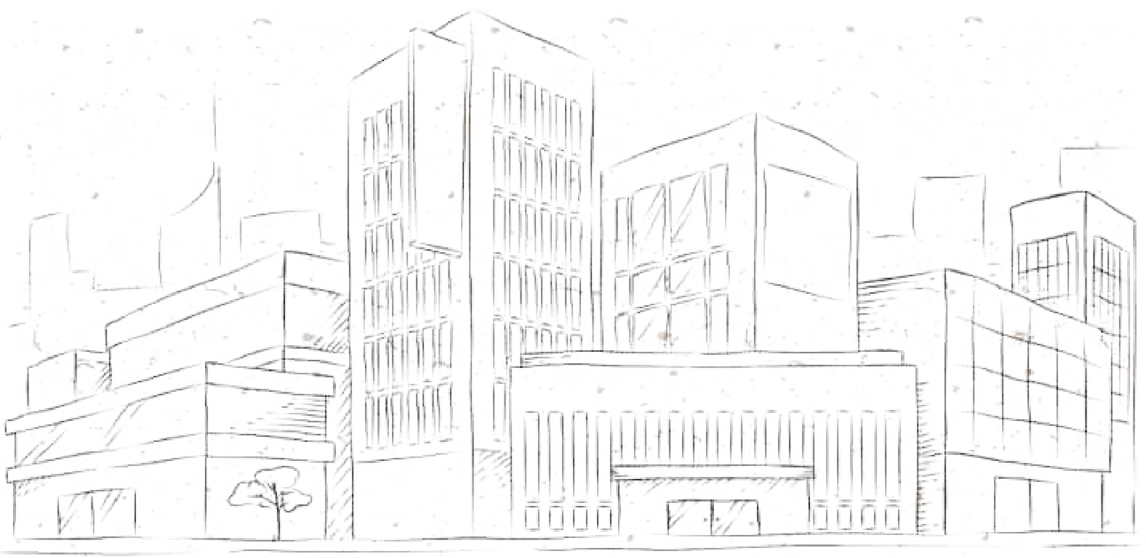

शब्दार्थ

सूचना एवं प्रचार निदेशालय, दिल्ली सरकार
ब्लॉक - 9, पुराना सचिवालय
दिल्ली-110054

दिल्ली

प्रधान संपादक

मनोज कुमार द्विवेदी
निदेशक, डी.आई.पी

संपादक

आलोक रंजन

सहायक संपादक

प्रवीण मिश्रा
गोविन्द राम

विशेष आभार

मनीष सिसोदिया
शिक्षा मंत्री, दिल्ली

गरिमा गुप्ता, आईएएस
सचिव, सूचना एवं प्रचार निदेशालय

लेआउट डिज़ाइन

हरिओम वशिष्ठ

ग्राफ़िक्स एंड फोटो

अजय कुमार शर्मा
अभिषेक हरित
पारूल शर्मा
कनिका थपलियाल

संपादकीय टीम

श्रीया
सुमित कुमार
महेंद्र कुमार
प्राची राठी

समन्वय

उमेश शर्मा
(अनुभाग अधिकारी-DIP)
दीपक कुमार दुआ
मनीष गंगावत
शरद मल्होत्रा
दिनेश कुमार
इन्द्रपाल सिंह
राजेश दुबे

वित्त प्रबंधन

जी.वी.आर. मुरली
कृष्ण कुमार

समग्र विकास का चिंतन

दिल्ली को काम पसंद है। तरक्की और खुशहाली, यहां का मूलमंत्र है। केजरीवाल सरकार के काम पर दिल्ली लगातार भरोसा जता रही है। सरकारी स्कूलों की बेहतर पढ़ाई ने साबित किया कि सच्ची देशभक्ति यही है। हर दिन बेहतर होती एजुकेशन क्वालिटी लगातार ये भरोसा दे रही है कि दिल्ली सरकार के स्कूल विश्व स्तरीय शिक्षा की ओर अग्रसर हैं। सस्ती और मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, प्रदूषण से युद्ध, मोहल्ला क्लीनिक जैसी योजनाओं की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। दिल्ली में महिलाओं के लिए मुफ्त बस सफर को भी काफी सराहा जा रहा है।

दिल्ली में रहने वालों का जीवन खुशहाल हो, यही प्राथमिकता दिल्ली सरकार की शुरूआत से रही है और आने वाले सालों में भी यही रहेगी। कच्ची कॉलोनियों में रहन–सहन का स्तर सुधारने से लेकर अनाधिकृत कॉलोनियों की सही व्यवस्था करने तक दिल्ली सरकार आम लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं को सबसे पहले ध्यान में रखती है। कोरोना काल की वजह से लगे लॉकडाउन के बाद ऑटो चालकों को सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गयी। इसके तहत उन्हें अपने बैंक के खाते में सीधे 5 हजार रुपये प्राप्त हुए हैं। दिल्ली में करीब 72 लाख लोगों तक मुफ्त राशन की योजना पहुंचायी गयी और यही चिंतन सरकार की वेलफेयर स्टेट की सोच को परिपूर्ण करती है। दिल्ली सरकार लगातार प्रयासरत है कि आने वाले दिनों में रोजगार सृजन के और भी अवसर सुनिश्चित किये जाएं।

कोरोना ने पूरे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को एक सबक दिया है। हर कोई इससे सीख लेने का प्रयास कर रहा है, हालांकि दिल्ली सरकार की प्राथमिकता में स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी जैसी बुनियादी जरूरतें शामिल हैं लेकिन इस प्रचंड महामारी से दिल्ली ने भी सबक सिखा है। मोहल्ला क्लीनिक, पॉली क्लीनिक के अलावा सरकार सभी अस्पतालों में बेड बढ़ाने पर लगातार काम कर रही है। मौजूदा समय में 500 से ज्यादा मोहल्ला क्लीनिक सेवा में लगे हैं और सरकार ने अब नए 100 महिला मोहल्ला क्लीनिक बनाने का प्रस्ताव पेश किया है। अब तक दिल्ली के अस्पतालों में 27 ऑक्सीजन प्लांट लगाये जा चुके हैं। दिल्ली में कुल 64 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की योजना है। स्वास्थय सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए दिल्ली का स्वास्थय विभाग लगातार काम में जुटा है। यहां तक की पशुओं की देखभाल के लिए भी दिल्ली सरकार ने अपने क्लीनिकों में सुविधाएं दी हैं।

दिल्ली सरकार की प्राथमिकता में यमुना की सफाई का काम महत्वपूर्ण है। खास तौर पर जो काम अब होना है वो है दिल वालों की दिल्ली में साफ हवा और शुद्ध पानी। साथ ही बेहतर स्वास्थ्य और उत्तम शिक्षा उपलब्ध कराना। दरअसल ये केजरीवाल सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं।

आलोक रंजन
संपादक

अंदर के पन्नों पर

1 बदलती दिल्ली

6 रोज़गार के लिए नए कोर्स

11 सजग और सेहतमंद दिल्ली

16 24 घंटे साफ पानी देने की तैयारी

20 शुद्ध हवा के लिए एक्शन प्लान

24 हर घर सस्ती बिजली

29 होगी सरकार आपके द्वार

32 चलो मुसाफिर

36 देशभक्ति करिकुलम लागू

40 खूब खेलेगी दिल्ली

44 आजादी उत्सव के रंग

बदलती दिल्ली

निरंतर विकास

विकास के मायने हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकते हैं, लेकिन इसका बुनियादी उद्देश्य सबके लिए एक ही है। ऐसे हर काम, जो एक साधारण व्यक्ति को सहूलियत दे और उनके जीवन को बेहतर बनाये, वो विकास है। एक स्टूडेंट के लिए विकास का मतलब अच्छे स्कूल, कॉलेज और शिक्षा व्यवस्था हो सकता है, एक युवा के लिए विकास के मायने रोजगार हो सकता है और एक आम आदमी के लिए विकास का अर्थ सस्ती बिजली, साफ पानी, बेहतर सड़क और जिंदगी जीने के लिए सारी मूलभूत चीजें आसानी से प्राप्त करना हो सकता है।

दिल्ली में विकास की बयार बह रही है। सरकार की कई सारी योजनाएं दिल्ली को नई दिशा दे रही हैं। दिल्ली के सामने प्रदूषण, जलजमाव, भूजल स्तर का कम होना, कचरे का निस्तारण जैसी कई बड़ी चुनौतियां है। इसलिए दिल्ली सरकार ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए कई बड़ी योजनाएं शुरू की हैं। दिल्ली में देश का सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है। यह एसटीपी 110 एकड़ में फैला होगा और प्रतिदिन 564 मिलियन लीटर (एमएलडी) की क्षमता से सीवेज को ट्रीट करेगा। इसे 2022 के अंत तक पूरा कर दिया जाएगा। इस एसटीपी के पूरा होने के बाद, यमुना में बहने वाले सीवेज का एक बड़ा हिस्सा साफ हो जाएगा। इस ट्रीटेड पानी का उपयोग भू-जल को फिर से बढ़ाने के लिए किया जाएगा, जबकि बाकी बचा हुआ

साफ पानी यमुना में छोड़ा जाएगा। इसके अलावा दिल्ली सरकार यमुना में इंटर स्टेट प्रदूषण को रोकने के लिए मास्टर–प्लान भी बना रही है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार अपने सभी कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) की क्षमता बढ़ाने की योजना बना रही है। इनका इस्तेमाल अधिकतम क्षमता पर किया जाए तो यमुना में गिरने वाले प्रदूषित पानी को काफी हद तक कम किया जा सकता है। दिल्ली में 29 औद्योगिक क्लस्टर हैं। इन 29 क्लस्टरों में 13 कॉमन एफ्लुएंट

ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) हैं, जो अपनी अधिकतम क्षमता पर 212 एमएलडी औद्योगिक कचरे को साफ कर सकते हैं। मौजूदा समय में ये सीईटीपी लगभग 50–55 एमएलडी औद्योगिक कचरे का ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जल मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि यमुना में बहने वाले औद्योगिक कचरे को साफ करने के लिए, सभी उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जाएगा। साथ ही शहर की 15 झीलों, 225 जलाशयों और आधुनिक कुओं को जीवंत करने का काम चल रहा है, जिससे दिल्ली के अंडरग्राउंड वाटर लेवल में बढ़ोतरी हो सके।

दूसरी तरफ प्रदूषण के खिलाफ विंटर एक्शन प्लान को भी तैयार करना शुरू कर दिया गया है। दिल्ली के आसपास के इलाकों में पराली जलाने से सबसे ज्यादा प्रदूषण का सामना करना पड़ता है। इसलिए विंटर एक्शन प्लान पराली व कूड़ा जलाने, वाहन व धूल प्रदूषण, हॉटस्पॉट, स्मॉग टावर वाररूम व ग्रीन एप को एडवांस बनाने जैसे बिंदुओं को आधार बनाकर काम करेगा। दिल्ली की हवा को शुद्ध बनाने के लिए दिल्ली के कनॉट प्लेस में देश के पहले स्मॉग टावर की शुरूआत की गई है। ये स्मॉग टावर हवा में प्रदूषण की मात्रा को कम करेगा। प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की शुरुआत की गई है। इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य दिल्ली मॉडल के तहत दिल्ली की अर्थव्यवस्था को गति देना और प्रदूषण को कम करना

है। दिल्ली में 2024 तक जितने भी नए वाहन पंजीकृत होंगे, उसमें से 25 प्रतिशत इलेक्ट्रिक होंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। टू व्हीलर, ऑटो रिक्शा व ई–रिक्शा खरीदने पर 30 हजार रुपये और कार पर 1.5 लाख रुपये इंसेंटिव मिलेगा।

दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए हाल में ही निजी निर्माण एजेंसियों के साथ बैठक की और धूल प्रदूषण को रोकने के लिए जारी 14 सूत्रीय दिशा–निर्देशों का पालन करने के सख्त निर्देश दिए। इन 14 निर्देशों में निर्माण स्थल को चारों तरफ से कवर करना होगा, 20 हजार वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में निर्माण या ध्वस्तीकरण हो रहा हो तो वहां पर एंटी स्मॉग गन लगाना जरूरी होगा और निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों को पूरी तरह से ढकना जैसे बिंदु शामिल हैं।

विकास के लिए महत्वपूर्ण है – अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं। कोरोना ने पूरी दुनिया को मजबूत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत को समझा दिया है। दूसरी लहर में अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड की कमी सबसे बड़ी चुनौती रही। इस दिशा में दिल्ली सरकार ने गंभीरता दिखाई और 7 नए हॉस्पिटल बनाए जाने के लिए तुरंत ही फैसला लिया ये अस्पताल – सरिता विहार, शालीमार बाग, सुल्तानपुरी, किराड़ी, रघुबीर नगर, जीटीबी अस्पताल और चाचा नेहरू

बाल चिकित्सालय में बनाए जा रहे हैं। मौजूदा अस्पतालों के नवीनीकरण और रीमॉडल के कारण अगले 2 वर्षों के भीतर दिल्ली में कुल 7,000 नए हॉस्पिटल बेड की सुविधा भी दी जायगी। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने अस्पतालों में बिस्तर बढ़ाने, स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या बढ़ाने, पीएसए ऑक्सीजन के विकास और बाल चिकित्सा कार्यबल जैसे कई और भी कदम उठाए हैं। दिल्ली के लोगों के लिए एक नया व्हाट्सएप कोविड हेल्पडेस्क नंबर जारी किया है जिससे उन्हें घर बैठे वैक्सीन, टेली–कंसल्टेशन और ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलिंग केन्द्रों की जानकारी मिल सकेगी। मोहल्ला क्लिनिक सबसे सफल उदाहरण है दिल्ली की स्वास्थय सेवाओं का, जहां पर लोग आसानी से अपने घर के पास स्वास्थय सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। महिलाओं की सेहत को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार महिला मोहल्ला क्लिनिक भी खोलने जा रही है। शुरूआती दौर में महिला समर्पित 100 मोहल्ला क्लिनिक खुलने जा रहे हैं।

लोगों की सहूलियत के लिए दिल्ली सरकार ने डोर स्टेप डिलीवरी शुरू की, जिसमें दिल्ली वालों को घर बैठे 150 से अधिक सरकारी सेवाएं मिल रही हैं। इसके लिए सरकार ने 1076 टोल फ्री नंबर जारी किया है, जिसे डायल कर के अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। यह योजना 2018 में शुरू की गयी थी, और अब इसकी अवधि पूरी होने के बाद इसे दोबारा से शुरू करने की मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है।

देश–विदेश में दिल्ली शिक्षा मॉडल को सराहा गया। सरकारी स्कूलों का कायाकल्प और क्वालिटी एजुकेशन के बेजोड़ मेल ने बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों

को पीछे छोड़ दिया है। जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण दो लाख से ज्यादा बच्चों का प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर,सरकारी स्कूलों में पंजीकृत कराना है। स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, योगा यूनिवर्सिटी और दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान को शुरू किया गया जो पारंपरिक एजुकेशन पैटर्न से अलग हट कर हैं।

इसके साथ दिल्ली को यूरोप की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है। इस तर्ज पर बीआरटी रोड (चिराग दिल्ली से शेख सराय) का सौंदर्यीकरण कार्य पूरा कर दिया गया है। यह सड़क आधुनिकता के साथ–साथ राष्ट्रवाद की झलक भी पेश करती है। चिराग दिल्ली से शेख सराय तक की इस सड़क का सौंदर्यीकरण पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हुआ है। साथ ही चांदनी चौक को कुछ इस तरह से खूबसूरत बनाया गया है कि अब ये दिल्ली के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल हो गया है। यहाँ सड़कों का चौड़ीकरण, पैदल यात्रियों के लिए शौचालय, पानी, एटीएम और कूड़ेदान जैसी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा दिव्यांगों के लिए यूनिसेक्स शौचालय और रैंप का प्रावधान किया गया है। अंडरग्राउंड केबल, सीवरेज सिस्टम और कॉम्पैक्ट ट्रांसफार्मर भी लगाया गया है।

इन तमाम योजनाओं के बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में दिल्ली मॉडल को पूरे देश में कैसे अपनाया जाता है।

रोज़गार के लिए नए कोर्स

दिल्ली सरकार बच्चों में एंटरप्रेन्योर बनने के गुण तराश करेगी। सरकारी स्कूलों में एंत्रप्रन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम के तहत बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 11 वीं और 12 वीं के हर बच्चे को 2 हजार रुपए सीड मनी दी जाएगी। दिल्ली में करीब 3.5 लाख छात्रों को इसका फायदा मिलेगा।

बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम पायलट प्रोजेक्ट के तहत स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खिचड़ीपुर में शुरू किया गया था। इसका मकसद बच्चों में ये विश्वास जगाना है कि वे जो भी काम करें, एंत्रप्रन्योरशिप माइंडसेट के साथ करें। इसमें 41 बच्चों के 9 ग्रुप बने और हर बच्चे को 1–1 हजार रूपये की सीड मनी दी गई और इन बच्चों ने जमकर मुनाफा कमाया। पायलट फेज में ये प्रोग्राम काफी सफल रहा है।

शिक्षामंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि आज देश में बेरोजगारी की जो समस्या है उसका एक मात्र उपाय एंत्रप्रन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम है। दिल्ली के बच्चे एंत्रप्रन्योरशिप माइंडसेट के साथ अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉब सीकर के बजाय जॉब प्रोवाइडर बनकर इस समस्या को दूर करेंगे।

दिल्ली सरकार ने 2019 में दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों के क्लासेज में एंत्रप्रन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम

की शुरुआत की थी। इस करिकुलम के पीछे मकसद था कि स्कूलों और कॉलेजों से पढ़ाई पूरी करने के बाद बच्चे नौकरी के लिए दर दर ना भटकें और ये मानसिकता बनाएं कि उन्हें जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब प्रोवाइडर बनना है। इस तरह देश की अर्थव्यवस्था में वे योगदान देंगे। अगर वो जॉब की तलाश में जाएं तो उनमें इतनी योग्यता हो कि उन्हें नौकरी की लाइन में न लगना पड़े बल्कि नौकरी उनके पास आए।

स्कूलों में अपनाने की जरूरत है।

स्कूलों में मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लैंग्वेज, सोशल–साइंस तो पढ़ाया जाता है लेकिन एंट्रेप्रेंयूरिअल माइंडसेट विकसित नहीं कर पाते हैं। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के तहत बच्चों को 2 हजार रुपये की सीड मनी दी जाएगी, जिससे बच्चों के अंदर से निवेश करने, बिजनेस शुरू करने का डर निकले। इसमें उन्हें प्रॉफिट कमाने के लिए तैयार करना है साथ ही अगर वे मुनाफा नहीं

इस तरह एक समय के बाद दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की तरफ से ये सन्देश पूरे देश में जाएगा कि बेरोजगारी को खत्म करने व अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का समाधान केवल एंत्रप्रन्योरशिप माइंडसेट है जिसे पूरे देश के सभी

भी कमाते हैं तो वे अपने फेलियर का सामना करना सीखें।

शिक्षामंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि आने वाले दिनों में जोनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ईएमसी के अंतर्गत बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोजेक्ट से 100 टॉप

प्रोजेक्ट्स के साथ ईएमसी कार्निवाल का आयोजन किया जाएगा। इसमें सफल एंटरप्रेन्योर और मशहूर विश्वविद्यालयों के द्वारा हुनरमंदों को मूल्यांकित किया जाएगा। इनमें टॉप 10 प्रोजेक्ट्स में शामिल बच्चों को एनएसयूटी और डीटीयू में बीबीए कोर्स में सीधे दाखिला दिया जाएगा।

हम होंगे कामयाब

विकसित देशों में पढ़ाई का तरीका अलग है, वहां स्किल पर जोर दिया जाता है। आज 21वीं सदी में अगर परंपरागत विषयों पर निर्भर रहे तो काफी पीछे छूट जाएंगे। आज जब पूरी दुनिया खुद को आगे करने की होड़ में लगी हुई है, तो दिल्ली सरकार ने भी इस क्रम में अपने कदम मजबूती से आगे बढ़ाये हैं। दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी (DSEU) के जरिये दिल्ली सरकार बच्चों में भविष्य के एंटरप्रेन्योर तैयार करेगी। सरकार दिसम्बर–जनवरी के महीने में स्कूलों में जाकर वहां एक एप्टीट्यूड टेस्ट लेगी और उसके आधार पर बच्चों को डीएसईयू में दाखिला मिल जाएगा। यहां पर दाखिले के लिए नम्बरों की रेस में नहीं भागना होगा बल्कि एप्टीट्यूड टेस्ट द्वारा उन्हें दाखिला मिलेगा। कैंपस सेलेक्शन की तर्ज पर कैंपस एडमिशन होगा। एडमिशन के लिए बच्चों को परीक्षा में मार्क्स का इंतज़ार नहीं करना होगा। जो बच्चे पढ़ाई के साथ–साथ अपने व्यक्तित्व के 360 डिग्री विकास पर ध्यान केंद्रित रखते हैं उन बच्चों को ध्यान में रख कर ही ये तरीका अपनाया गया है। ये यूनिवर्सिटी पहले सत्र में 6000 विद्यार्थियों को दाखिला देगी।

डीएसईयू में छात्रों के बहुआयामी व्यक्तित्व के विकास पर जोर दिया जाएगा। देश में ये पहली बार है कि कोई यूनिवर्सिटी इस तरीके से एडमिशन देगी। हालांकि विदेशों में टॉप यूनिवर्सिटी और संस्थान

दिल्ली के सरकारी स्कूल के ग्यारहवीं क्लास के 8 बच्चों ने स्टार्टअप शुरू किया जिसमें वे पुराने फोन को मरम्मत कर फिर से उसे रिसेल करते हैं। इसमें उन्होंने आठ हजार इनवेस्ट किए और बदले में उन्हें 21,960 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अभी तक ये लोग 12 रीफर्बिश फोन बेच चुके हैं। सुख सागर जो कि इस टीम का हिस्सा हैं, वो बताते हैं कि उन्होंने अपनी गली के लोगों से संपर्क किया कि जो भी उनके पुराने फोन हैं उनका वो सही रेट लगा कर ले लेंगे। इसके साथ उन्होंने एक दुकान खोजी जहां पर उन्हें उन मोबाइल फोनों को सही करने के लिए इक्विपमेंट मिल गये।

इस टीम में सभी के काम बंटे हुए हैं, कोई कंटेंट मैनेज करता है जो प्रमोशन के काम में आता है, तो दूसरा टीम मेम्बर मोबाइल फोन की फ़ुर्बिनिशिंग करता है, सोशल मीडिया हैंडलिंग भी इनमें से कोई संभालता है और इनमें से ही कोई एक एप या वेबसाइट भी बनाता है।

इसी तरह के एप्टीट्यूड टेस्ट के आध ाार पर एडमिशन देते हैं। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि डीएसईयू का मकसद दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले हर एक बच्चे को ये कॉन्फिडेंस देना है कि उनकी आगे की पढ़ाई के लिए एक विश्वस्तरीय संस्थान तैयार है। उन्होंने कहा कि आज पूरे विश्व को स्किल्ड लोगों की जरूरत है, 21वीं सदी में हम ये कल्पना नहीं कर सकते कि हम अपने बच्चों को 20वीं सदी के विषय पढ़ाएं।

डीएसईयू दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को 21वीं सदी के कौशलों में पारंगत करेगा। वोकेशनल स्ट्रीम में पढ़ने वाले बच्चों को डीयू में दाखिला नहीं मिल पाता है। ऐसे बच्चों के मन में हमेशा ये सवाल होता है कि वोकेशनल की पढ़ाई करके हम कहां जाएं। डीएसईयू अब उन विद्यार्थियों को ये कांफिडेंस देगा कि वो वोकेशनल की पढ़ाई जारी रखें और उन्हें ये कॉन्फिडेंस होगा कि उनकी आगे की पढ़ाई के लिए एक यूनिवर्सिटी अपने दरवाजे खोलकर बैठी है।

इसके साथ ही यह यूनिवर्सिटी महिला

सशक्तिकरण पर भी जोर दे रही है। डीएसईयू ने नवगुरुकुल फाउंडेशन फॉर सोशल वेलफेयर के साथ करार किया है। जिसके तहत सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में 20 महीने का एडवांस कोर्स कराया जाएगा। 17—30 आयु वर्ग के बीच की दिल्ली की महिलाएं और ट्रांसजेंडर महिलाएं इस प्रोग्राम में आवेदन कर सकती हैं। कोडिंग सिखाना और सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना इस प्रोग्राम का उद्देश्य है।

कल बनाएंगे बेहतर, देश के मेंटर

देश के मेंटर प्रोग्राम के जरिये बच्चों का करियर संवारने की पहल की गई है। यह सपना देश भर के सफल हस्तियों की मदद से साकार होगा। ये कार्यक्रम 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए शुरू किया गया है। जिससे उनकी करियर को सही दिशा मिले। मेंटर बच्चों को फोन पर रोजाना 10 से 15 मिनट तक गाइड कर सकते हैं। देश के किसी भी हिस्से में रहने वाला व्यक्ति दिल्ली सरकार के एप पर पंजीकरण कर मेंटर बन सकता है।

सजग और सेहतमंद दिल्ली

दिल्ली देश में हेल्थ हब बन कर उभर रही है, क्योंकि यहां एक मजबूत शहरी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली है। दिल्ली सरकार ने थ्री लेयर हेल्थ सिस्टम को डेवलप किया है। आज के समय में 500 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली–वासियों के लिए काम कर रहे हैं। दिल्ली शहर तेजी से देश के शीर्ष स्वास्थ्य केंद्रों में से एक बन रहा है।

मोबाइल मोहल्ला क्लिनिक

सबसे पहले बात करें मोहल्ला क्लिनिक की। इसकी चर्चा दुनिया भर में है। मोहल्ला क्लिनिक योजना राजधानी में हेल्थकेयर को आगे बढ़ाने और थ्री हेल्थकेयर सिस्टम में प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख के पहले स्तर को सुदृढ़ बनाने की बड़ी कोशिश है। इसकी शुरुआत ट्रायल के तौर पर 2016 में हुई और ये जल्द ही लोगों के बीच लोकप्रिय हो गई।

सभी फ्रंटो पर नयी दिशा में काम हो रहा है। दिल्ली सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक को अब नए रुप में तैयार किया है। नए मोहल्ला क्लिनिक पोर्टेबिलिटी के आधार पर बनाए गए हैं, नए मोहल्ला क्लिनिक बनाने के लिए पोर्टेबल कंटेनरों का इस्तेमाल हो रहा है। कंटेनरों से बने क्लिनिकों को जल्दी से इकट्ठा और अलग किया जा सकता है और तंग जगहों में आसानी से फिट किया जा सकता है। इस तरह

का पहला क्लिनिक शकूरपुर बस्ती में बनाया गया है।

मोहल्ला क्लिनिक के नए डिजाइन के पीछे का कांसेप्ट हवाई जहाज से लिया गया है, चेक–अप, दवा और परामर्श के लिए अलग–अलग स्पेस हैं। शिपिंग कंटेनर से बने इस तरह के दो मोहल्ला क्लिनिकों को अभी पायलट बेसिस पर बनाया गया है। मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। इसमें सभी मरीजों के लिए वन स्टॉप सेवाएं और रेफरल सेवाओं समेत आवश्यक सेवाएं मिलने तक, पूर्ण हैंड होल्डिंग प्रदान की जाती है।

पिछले चार वर्षों में 16.24 मिलियन से अधिक नागरिकों को मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाएं मिली हैं, जबकि 2.25 करोड़ मरीजों का इलाज दिल्ली सरकार के अस्पतालों और पॉलीक्लिनिक के माध्यम से किया गया है। कोविड–19 के चलते इस परियोजना को और ज्यादा बढ़ावा मिला है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा– 'ये क्लिनिक पोर्टेबल कंटेनरों में स्थापित किए गए हैं। ऐसे क्लिनिक झुग्गी–बस्ती और संकरी गलियों जैसे क्लस्टर क्षेत्रों में स्थापित करना और इन्हें वहाँ शिफ्ट करना आसान है जहां स्वास्थ्य सेवा का बुनियादी ढांचा कम सुलभ है।

उदाहरण के तौर पर दक्षिणी दिल्ली की शेख सराय निवासी, 42 वर्षीय मीनू वर्मा पिछले दो सालों से थायरॉइड और अस्थमा की दवाओं के लिए हर 20 दिनों में मोहल्ला क्लिनिक जाती हैं और नियमित रूप से चेकअप भी कराती हैं।

महिलाओं के लिए विशेष मोहल्ला क्लिनिक

कितना अच्छा लगता है कि जब आपको कोई सुविधा अपने घर के पास मिल जाए। आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक के सकारात्मक परिणाम और महिलाओं की स्थिति को समझते हुए, दिल्ली सरकार ने महिला मोहल्ला क्लिनिक बनाने का निर्णय लिया है, जो महिलाओं को उनके घरों से पैदल दूरी के भीतर मुफ्त स्त्री रोग और अन्य चिकित्सा सेवाएं प्रदान करेगा।

इन मोहल्ला क्लिनिकों में ज्यादातर डॉक्टर और नर्सेज महिलाएं होंगी। साल 2022 से महिलाओं को ये सुविधा आसानी से उनके घर के पास

शुरू हुए 27 PSA ऑक्सीज़न प्लांट

ही मिलेगी। अब लोग स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए मोहल्ला क्लिनिकों को प्राथमिकता देते हैं।

जब से दिल्ली की स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्था में क्रांति आई है तब से दिल्लीवासियों में परिवर्तन देखा गया है, डेंगू से लेकर महामारी तक दिल्ली ने हर स्तर पर अपने आप को प्रूव किया है। 10 सप्ताह का अभियान दिल्ली में डेंगू को नियंत्रित करने के लिए लाया गया। हर रविवार सुबह 10 बजे 10 मिनट के लिए घरेलू जगहों की जांच से जुड़े कार्यक्रमों को शुरू किया गया, जिसका परिणाम ये है कि साल 2019 –2021 तक डेंगू के केस तो आये हैं लेकिन कोई डेथ रिपोर्ट नहीं हुई।

मौजूदा अस्पतालों के नवीनीकरण और रीमॉडल के कारण अगले 2 वर्षों के भीतर दिल्ली में कुल 7,000 नए बेड जोड़े जाएंगे। राजधानी में आईसीयू बेड की क्षमता 70 फीसदी तक बढ़ जाएगी। प्राइवेट हॉस्पिटल की तर्ज पर ही सरकारी अस्पतालों में बदलाव होने जा रहा है जिसमें आईसीयू, आपातकालीन, ओपीडी, वार्ड ब्लॉक और पीएसए, ऑक्सीजन टैंक और बहु– स्तरीय कार

पार्किंग ब्लॉक के लिए जगह सहित सेवा भवन शामिल हैं।

स्पेशल टास्क फोर्स का गठन

दिल्ली सरकार ने तीसरी कोविड–19 लहर को कुशलता से संभालने के लिए दो विशेष कार्यबलों – बाल चिकित्सा विशेष कार्यबल और राज्य स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।

समुदाय आधारित स्वास्थ्य सहायता

चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति सहित, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को भी कोरोना की दूसरी लहर के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों की कमी का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि संकट के समय में स्वास्थ्य कार्यबल के रूप में इस्तेमाल किए जा सकने वाले 5000 यूथ को हेल्थ असिस्टेंट्स के तौर पर ट्रेनिंग दी जायगी जिससे तीसरी लहर पर काबू पाने में मदद मिलेगी। वे वर्तमान में दिल्ली के नौ अस्पतालों में ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं कि कैसे महामारी, जीवन रक्षक उपचार और होम विजिट से संबंधित गंभीर परिस्थितियों को संभालना है।

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान

दिल्ली ने कोविड–19 वेव थ्री के लिए अपनी तैयारियों के तहत एक ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) तैयार किया है। योजना के तहत चार प्रकार के स्तर और कलर–कोडेड अलर्ट सिस्टम प्रस्तावित किए गए हैं। कोविड सकारात्मकता दर के आधार पर, चार रंग कोडों की पहचान की गई है: पीला, एम्बर, नारंगी और लाल।

दिल्ली सरकार अब तैयार है हर तरीके से दिल्ली वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें देने के लिए। अब लोगों में बड़े बिलों के खौफ और बीमारियों की जगह एक नयी सोच पैदा हुई है, जो उन्हें स्वास्थ्य के प्रति और ज्यादा सजग रहने के लिए प्रेरित करती है।

मेन्टल वेल बीइंग – अब कोई स्ट्रेस नहीं

हर कोई सिर्फ फिजिकल हेल्थ के बारे में ही सोच रहा है, लेकिन देखा जाए तो महामारी का सबसे ज्यादा असर तो हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ा है। दिल्ली सरकार अपनी नयी सोच और आईडिया के लिए जानी जाती है। मेन्टल वेल बीइंग, एक नया एक्सेक्यूशन, युवा हेल्पलाइन द्वारा लांच किया गया। एक समय ऐसा भी आया– जब लोगो को कोरोना संक्रमण का डर, नौकरी–पढ़ाई और जीवनशैली में बदलाव का सामना करना पड़ा। मायूसी और अकेलेपन का शिकार हो चुके लोगों के लिए सरकार ने प्रोफेशनल काउंसलर की सहायता दी। उप–मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसे लेकर कहा कि दिल्ली के सभी नागरिक सरकार से संपर्क कर सकते

हैं। कोई भी छात्र जो तनाव में है या उदास महसूस कर रहा है, उसे दिल्ली सरकार की युवा हेल्पलाइन पर कॉल करना चाहिए। हमारे काउंसलर लोगों की काउंसलिंग का काम करेंगे। इस युवा हेल्पलाइन (1800–11688/10580) का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कॉलेज छात्रों और नौकरीपेशा लोगों ने किया और एक अच्छा परिणाम सामने आया। कोरोना जिस समय अपने चरम पर था उस वक्त इस युवा हेल्पलाइन पर प्रतिदिन 200– 250 कॉल औसतन आती थी।

डिजिटल और क्लाउड आधारित हेल्थ सिस्टम

हेल्थ कार्ड प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली के निवासियों को वोटर आईडी और जनसंख्या रजिस्ट्री के आधार पर क्यूआर कोड आधारित ई–हेल्थ कार्ड जारी किए जाएंगे। दिल्ली सरकार जल्द से जल्द दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों को ऑनलाइन पोर्टल से लिंक करने जा रही है। बाद में निजी अस्पतालों को भी चरणबद्ध तरीके से इससे जोड़ा जाएगा। मरीज़ से संबंधित सेवाएं जैसे – बैंक एंड सर्विसेज़, बज़ट एवं अस्पताल प्रशासन को इस प्रणाली के तहत लाया जाएगा। इससे दिल्ली के लोगों को एक ही छत के नीचे सारी जानकारी मिल सकेगी। इसके बाद दिल्ली सरकार देश की एकमात्र ऐसी सरकार बन जाएगी, जिसके पास क्लाउड आधारित स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली होगी। वर्तमान में स्वीडन, युगांडा और जर्मनी जैसे कुछ विकसित देशों में ऐसी प्रणाली उपलब्ध है।

महामारी से सबक लेते हुए दिल्ली सरकार ने दिल्ली को सेहतमंद बनाने के प्रयास को एक नयी दिशा दी है। दिल्ली विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रही है जिसका श्रेय दिल्लीवासियों को भी जाता है।

24 घंटे साफ पानी देने की तैयारी

दिल्ली में भूजल स्तर को बनाये रखने के लिए दिल्ली सरकार कई तरह से पहल कर रही है। शहर की 15 झीलों, 225 जलाशयों और आधुनिक कुओं को जीवंत करने का काम चल रहा है।

दरअसल दिल्ली सरकार महानगर को झीलों का शहर बनाने की ओर बढ़ रही है जिसके तहत 15 झीलों और 225 जलाशयों को जीवंत किया जा रहा है। इससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज में काफी मदद मिलेगी और लोगों को पानी की समस्या से निजात मिलेगी। साथ ही साथ आधुनिक कुओं के जरिए भी जलापूर्ति की तैयारी है।

कुएं का उपयोग प्राचीन काल से ही पानी की आपूर्ति के लिए किया जाता रहा है। आज 21वीं सदी में भी कुएं का उपयोग जल आपूर्ति के लिए करना बड़ा ही रोचक है। सरकार 24 घंटे पानी मुहैया कराने के लिए इनोवेशन

का इस्तेमाल कर रही है। दिल्ली सरकार सोनिया विहार और अक्षरधाम में आधुनिक कुओं का निर्माण कर रही है। इन कुओं के बनने के बाद हर दिन 90 लाख लीटर पानी जमीन से निकाला जा सकता है। इस साल के अंत तक इन कुओं के निर्माण को पूरा करने और इसे पूरी तरह से चालू करने की समय सीमा तय की गयी है।

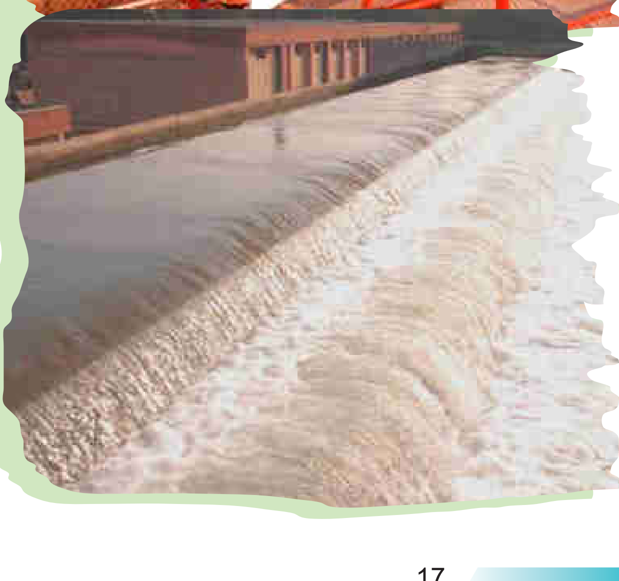

इसके अलावा दिल्ली सरकार बवाना में 6 एकड़ भूमि पर सनोथ झील को आधुनिक तकनीकों के साथ पुनर्जीवित कर रही है। सनोथ झील को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य इस साल दिसंबर तक का रखा गया है। 6 एकड़ में फैली सनोथ झील बवाना के सनोथ गांव में स्थित है। बवाना कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) से लगभग 3 एमजीडी पानी को रिसाइकल करके इस झील को जीवंत करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। इस झील के आस–पास बच्चों के लिए खेल का मैदान, पिकनिक गार्डन, पैदल मार्ग, छठ पूजा

घाट और जिम जैसी सुविधाएं आम जनता के लिए होंगी। सनोथ झील के बनने से न केवल भूजल को रिचार्ज करने में मदद मिलेगी बल्कि इस क्षेत्र में एक 'इकोसिस्टम' का भी निर्माण होगा।

इसी तरह महरौली के संजय वन की झील को भी नया जीवन मिला है। डीडीए के अंतर्गत आने वाली इस झील के पानी को साफ करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने इसमें फ्लोटिंग राफ्टर्स डाले थे। ये ऐसे पौधे होते हैं जो पानी के प्रदूषण को सोख लेते हैं।

सोचा है कभी अगर धरती पर पीने को पानी नहीं बचा तो क्या हाल होगा? हर जगह त्राहिमाम मचा होगा। शायद इसलिए अब पानी के प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब पानी के लिए तीसरा विश्व युद्ध लड़ा जाएगा।

घोगा ड्रेन में प्राकृतिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) में गंदे पानी को साफ करने की क्षमता को 10 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर 50 लाख लीटर प्रतिदिन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। यह एसटीपी वेटलैंड प्रणाली पर आधारित है और बिना बिजली के प्रतिदिन 10 लाख लीटर गंदे पानी को साफ करता है। रिसाइकल किये गए पानी का उपयोग नजदीक के क्षेत्र में एक झील बनाकर भूजल को रिचार्ज करने के लिए किया जाएगा। यह कहना है सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के मंत्री सत्येंद्र जैन का। बवाना एस्केप ड्रेन की सफाई के लिए दिल्ली

RO वाटर

नजफगढ़ इलाके में पानी 2–3 मीटर की गहराई पर मौजूद है, लेकिन खारेपन की वजह से इस पानी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ऐसी ही दिक्कत दिल्ली के कई इलाकों में है। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए दिल्ली सरकार ने राजधानी में रिवर्स ऑस्मोसिस (आरओ) प्लांट लगाने जा रही है। ये योजना उन जगहों पर लागू की जाएगी, जहां पर भूजल स्तर अधिक है पर खारेपन और टीडीएस के वजह से उस पानी का उपयोग नहीं हो पाता है। आमतौर पर जब भी पानी प्यूरीफाई किया जाता है तो इस प्रक्रिया में मशीन से बहुत सारा पानी बर्बाद होता है पर इस अत्याधुनिक तकनीक से बने आरओ मशीन से 80 फीसदी कम पानी बर्बाद होगा। शुरुआती दौर में 363 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) की कुल क्षमता वाले आरओ मशीन लगाए जाएंगे। इन आरओ प्लांटों में पानी की आपूर्ति जमीन से पानी निकालकर की जाएगी, जिसके बाद घरों में शुद्ध पानी पहुंचाया जाएगा। इस परियोजना के पहले चरण में ओखला, द्वारका, नीलोठी–नांगलोई, चिल्ला और नजफगढ़ को चुना गया है। दिल्ली सरकार ने इस परियोजना को एक साल के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा है।

स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (डीएसआईआईडीसी) और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग (आई एंड एफसी) को जिम्मेदारी दी गयी है।

यमुना नदी की सफाई दिल्ली सरकार की मुख्य सूची में शामिल है। यमुना में बहने वाले प्रमुख नालों के कायाकल्प और सौंदर्यीकरण इसी दिशा में किए जा रहे हैं। इनमें नजफगढ़, सप्लीमेंट्री और शाहदरा सहित कुछ ऐसे नाले हैं जिन्हें साफ और सुंदर बनाया जाएगा। सभी प्रमुख नालों को फिर से साफ पानी के चैनलों में बदला जाएगा। फिलहाल ये नाले सूखे कूड़े, कीचड़ और गंदे पानी की वजह से प्रदूषित हैं। नालों से निकलने वाली दुर्गंध व वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में जैविक गंध नियंत्रण प्रणाली और नालों में फ्लोटिंग एयररेटर स्थापित किये जायेंगे। शहर की जल निकासी व्यवस्था को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए राजधानी के सभी नालों को ड्रेनेज मास्टर प्लान के तहत बेहतर और पुनर्निर्मित किया जाएगा। चौबीसों घंटे जलापूर्ति और यमुना की सफाई, दिल्ली सरकार की पहली प्राथमिकता है।

इन तमाम परियोजनाओं के अलावा पानी की जरूरत और इसके प्रति हर एक व्यक्ति की यह जिम्मेदारी बनती है कि इसे कैसे बचाया जाए। बेवजह पानी की बर्बादी अगर हम रोक सकते हैं तो उसे रोकना चाहिए। सरकार के अलावा यह हर इन्सान का भी दायित्व है।

शुद्ध हवा के लिए एक्शन प्लान

वायु प्रदूषण सेहत, अर्थव्यवस्था और जलवायु के लिए एक बड़ा खतरा है। 'प्रदूषण के खिलाफ युद्ध' को ज्यादा असरदार बनाने और दिल्ली को प्रदूषित हवा से मुक्ति दिलाने के लिए दिल्ली के कनॉट प्लेस में देश के पहले स्मॉग टावर की शुरूआत की गई। ये स्मॉग टावर अमेरिकी तकनीक से बना है और ये हवा में प्रदूषण की मात्रा को कम करेगा। इस प्रोजेक्ट का ट्रायल सफल रहा है और 1 अक्टूबर से ये स्मॉग टॉवर पूरी क्षमता के साथ काम कर रहा है। इस टॉवर की प्राथमिक रिपोर्ट में यह सामने आया है कि यह टॉवर 80 प्रतिशत तक हवा को साफ कर रहा है। यह 24 मीटर ऊंचा टावर है। ये स्मॉग टॉवर ऊपर की तरफ से आसपास के एक किलोमीटर के दायरे की हवा को खींचेगा और फिर उस हवा को साफ करेगा। इसके बाद इसमें नीचे के तरफ लगे हुए पंखे उस शुद्ध हवा को नीचे से बाहर छोड़ेंगे। इसकी क्षमता लगभग एक हजार घन मीटर प्रति सेकेंड है, यानि ये स्मॉग टॉवर एक हजार घन मीटर हवा प्रति सेकेंड साफ करके बाहर छोड़ेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज तक देश में कहीं भी ऐसा टावर लगाकर प्रदूषित हवा को साफ करने का कभी प्रयास नहीं किया गया। हमारा ये नया कदम मील का पत्थर साबित होगा।

आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमिटी के वैज्ञानिक इस डाटा का विश्लेषण

करेंगे। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली सरकार ने स्मॉग टॉवर की मॉनिटरिंग करने के लिए 16 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। यह कमेटी तीन–तीन महीने के अंतराल पर तीन रिपोर्ट सरकार को देगी। अगर यह प्रयोग प्रभावी होगा, तो फिर इस तरह के और भी स्मॉग टावर पूरे दिल्ली के अंदर लगाए जाएंगे।

एयर क्वालिटी इंडेक्स हवा की गुणवत्ता के बारे में जानकारी देता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स मुख्य रूप से 8 प्रकार के प्रदूषणों ((PM10, PM2-5, NO2, SO2, CO, O3, NH3, and Pb)) को मापता है। दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या को भयंकर बनाने में मुख्य भूमिका हवा में मौजूद PM 2.5 और PM 10 कणों की होती है. जिस वजह से इन कणों का स्तर वायु में बढ़ जाता है तो सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन होने लगती है।

दिल्ली सरकार ने स्टेट लेवल इनवायरमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट अथॉरिटी (राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण) और स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी (राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति) के गठन को अधिसूचित कर दिया है। समिति बनने से आवेदनों का निस्तारण करने में आसानी होगी। परियोजनाओं की पर्यावरण मंजूरी के लिए अब केंद्र सरकार के फैसले का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके

विंटर एक्शन प्लान 2021

1. पराली के लिए डीकंपोजर
2. धूल विरोधी अभियान
3. कचरा जलाने पर जुर्माना
4. पटाखों पर प्रतिबंध
5. स्मॉग टॉवर
6. मॉनिटर हॉटस्पॉट
7. ग्रीन वॉर रूम
8. ग्रीन दिल्ली ऐप
9. भारत का पहला ई–वेस्ट पार्क
10. वाहनों के द्वारा उत्पन्न प्रदुषण पर रोक

स्मॉग टावर की विशेषताएं

- **स्मॉग टावर का प्लान एरिया– 28 X 28 मीटर। (784.5 वर्ग मीटर)**
- **टावर ऊपर से हवा खींचेगा और फिल्टर्ड हवा छोड़ेगा।**
- **पंखे के माध्यम से एक हजार घन मीटर प्रति सेकेंड फिल्टर हवा जमीन के पास छोड़ेगा।**
- **स्मॉग टावर का प्रभाव केंद्र करीब एक किलोमीटर के दायरे में है।**
- **इसमें कुल 40 पंखे लगे हैं।**
- **25 घन मीटर प्रति सेकंड वायु प्रवाह दर है।**
- **16.1 मीटर प्रति सेकंड फैन की आउटलेट वेलोसिटी**
- **कुल फिल्टर की संख्या 5000 है।**
- **ईएसएस की क्षमता 1250 केवीए है।**

साथ ही राज्य में पर्यावरण प्रभाव का आंकलन अधिक मजबूती और पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। दिल्ली के लिए राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) और राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) का गठन 3 साल के कार्यकाल के लिए किया गया है। पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता वाली 'बी' श्रेणी की परियोजनाओं को केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब दिल्ली सरकार द्वारा ही बिना विलम्ब किए मंजूरी दी जाएगी।

दिल्ली सरकार ने जलवायु परिवर्तन से होने वाले खतरे को देखते हुए दिल्ली में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए वृक्षारोपण नीति, एंटी– डस्ट प्रदूषण अभियान, इलेक्ट्रिक वाहन नीति, रेड लाइट ऑन–गाडी ऑफ जैसे कई कदम उठाए हैं। इसी क्रम में कई यूनिवर्सिटियों में पौधारोपण किया गया। इस साल दिल्ली सरकार ने 33 लाख पौधे लगाने का निर्णय लिया है।

इसके अतिरिक्त खास ये है कि दिल्ली सरकार जैविक डी–कंपोजर का प्रयोग करके पराली गलाने के उपायों पर प्रयोग करने वाली इस देश की पहली राज्य सरकार है।

दिल्ली को हरियाली और शुद्ध हवा देने के लिए राज्य सरकार की इन पहलों से यह देखना सुखद होगा कि कब पूरी तरह दिल्ली को शुद्ध हवा जीने के लिए मिले।

हर घर सस्ती बिजली

दिल्ली में सस्ती बिजली अब हकीकत है। डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार 2019 – 20 में 31 लाख मीटर धारकों का बिजली का बिल जीरो आया। वहीं 12 लाख लोगों को 200 से 400 यूनिट पर सब्सिडी देकर उनके बिल को आधा किया गया। दिल्ली सरकार दिल्ली के सभी लोगों के घरों को रोशन करने के लिए व्यापक कदम सरकार ने उठाए है। लोगों के घरों तक सस्ती बिजली पहुंचाने के लिए बिजली से जुड़े बुनियादी ढांचे को सरकार ने बदला है। नया मीटर लगाते समय किए जाने वाले भुगतान को भी सरकार ने काफी कम किया है। दिल्ली के ग्रामीण इलाके हों चाहे दिल्ली के शहरी क्षेत्र तमाम स्थानों पर 24 घंटे बिजली आज के समय में उपलब्ध रहती है। इस सरकार से पहले दिल्ली में बिजली की स्थिति बहुत ही जर्जर हालत में थी। अब हमें गलियों में माताएं, बहनें, बुजुर्ग हाथ वाला पंखा लिए नहीं दिखते हैं। हाथ वाले पंखों की जगह घरों से खत्म हो गई है। इससे पूर्व गर्मियों में लोग अपने घरों में विशेष तैयारियां कर के रखा करते थे। दिल्ली के अधिकांश लोग अपने घरों में जनरेटर रखते थे ताकि बिजली जाने के बाद जनरेटर का प्रयोग करके घर के सारे काम किए जा सकें लेकिन अब आपको रिहायशी घरों में जनरेटर बहुत ही कम देखने को

मिलेगा क्योंकि दिल्ली के लोग अब रात हो या दिन हमेशा बिजली का उपयोग कर पा रहे हैं।

राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली सरकार द्वारा बिजली के क्षेत्र में किए गए विकास कार्य की झलक हमें अनेक अवसरों पर देखने को मिलती है। इसका अनुसरण करते हुए देश के अन्य राज्य भी अपने यहां सस्ती बिजली देने का प्रयास कर रहे हैं। इस सरकार का मानना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी का ढांचा अगर मजबूत कर लिया जाए तो देश अपने आप ही विकास के मार्ग पर अग्रसर हो जाएगा। आपको बता दें दिल्ली में देश की सबसे सस्ती बिजली मिल रही है। सरकार की बिजली आधारित नीतियों से दिल्ली के गरीब, सामान्य व अमीर लोग बहुत खुश हैं। दिल्ली में 24 घंटे बिजली देने को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दिल्ली के लोगों को मिल रही है। करीब 90 प्रतिशत परिवार इसका फायदा ले रहे हैं। 201 से 400 यूनिट तक 50 प्रतिशत सब्सिडी मिल रही है। दिल्ली में मुख्यमंत्री किरायेदार बिजली मीटर योजना का विस्तार हुआ है। इससे दिल्ली में रह रहे किरायदारों को बहुत फायदा मिल रहा है। झुग्गियों में भी बिजली के स्थाई मीटर लग रहे हैं। प्रतिमाह 400 यूनिट बिजली खपत करने वाले 1984 के सिख विरोधी दंगा पीड़ित परिवारों का बिजली बिल माफ किया जा रहा है। दिल्ली के बाजारों में बिजली के तारों का जंजाल आम बात हुआ करती थी पर अब इन तारों के जंजाल को खत्म किया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण दिल्ली का चांदनी चौक है। इस बाजार में

लोगों के चलने की जगह नहीं होती थी, अब यहां लोग दौड़ सकते हैं। ये इलाका तारों के जंजाल से पटा होता था पर अब यहां की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। तारों के जंजाल को खत्म किया गया है। पूरे चांदनी चौक मार्केट में बिजली की सुचारु व्यवस्था बनाए रखने के लिए नए प्रयोग किए गए हैं। दिल्ली में बिजली चोरी पर अंकुश लगा

है। इसके लिए ऐसे तारों का प्रयोग किया गया जो प्लास्टिक के कवर द्वारा पूरी तरीके से पैक होती है। इससे पहले दिल्ली में लोहे के तार लोगों के घरों तक बिजली पहुंचाने में प्रयोग किए जाते थे जिससे आसानी से चोरी हो जाती थी।

दिल्ली सौर ऊर्जा के विस्तार का काम दिल्ली सरकार बहुत तेजी से कर रही है। सरकारी भवनों, स्कूलों, संस्थाओं और अदालत परिसरों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जा रहे हैं। दिल्ली के कई सरकारी स्कूल इस पहल में अग्रणी साबित हो रहे हैं। सौर ऊर्जा प्लांट लगाकर दिल्ली के कई सरकारी स्कूल अपना लाखों रुपए का खर्च बचा रहे हैं। दिल्ली सरकार साल 2016 में सौर ऊर्जा नीति लेकर आई थी। इसके तहत 2025 तक 2000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अभी दिल्ली में 169 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। इसके तहत दिल्ली में कई हाउसिंग सोसाइटी में सौर ऊर्जा प्लांट संयंत्र लगाए जा चुके हैं। सरकार इसके बदले सब्सिडी भी दे रही है। इसके अलावा दिल्ली सचिवालय, पुराना सचिवालय, विकास सदन, विश्वविद्यालयों की छतों पर भी सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है। सरकार का आवासीय परिसरों से 1250 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य है।

सोलर फार्मिंग के साथ खेती भी होती रहे इसलिए खेतों पर इसे 3.5 मीटर ऊपर लगाया जाएगा। इसके बदले किसानों को प्रति एकड़ एक लाख रुपये किराया भी मिलेगा। साथ ही एक हजार यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। किराये में हर साल बढ़ोतरी होगी। 2025 तक यह किराया चार लाख प्रति एकड़ तक पहुंच जाएगा। इसको लेकर जमीन के लिए किसानों से सहमति मिल चुकी है। दिल्ली में राजघाट पावर प्लांट को सरकार ने बीते साल ही आधिकारिक तौर से बंद करने की घोषणा कर दी थी। सरकार यहां पर सोलर एनर्जी पार्क बनाएगी। करीब 4.5 एकड़ में फैले इस पावर प्लांट से 5000 किलोवाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ये दिल्ली का पहला सौर ऊर्जा पार्क बनेगा। इसको लेकर तेजी से कार्य हो रहा है। वाहनों की चार्जिंग के लिये दिल्ली भर में सार्वजनिक जगहों पर 100 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किये जाने की योजना है। इसी कड़ी में डीटीसी नेहरू प्लेस बस टर्मिनल में पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लांट लगाया गया है।

'मुख्यमंत्री किरायेदार बिजली मीटर योजना'

दिल्ली की सस्ती बिजली दरों का फायदा किरायेदारों को नहीं मिल रहा

था, लेकिन अब वे 3,000 की सुरक्षा राशि जमा करके प्रीपेड मीटर लगवा सकेंगे और इसके लिए मकान मालिक से किसी तरीके की एनओसी लेने की जरूरत नहीं होगी। किरायेदार 19122, 19123, 19124 इन तीन नंबरों पर फोन करके बिजली कंपनियों से प्रीपेड मीटर मंगवा सकते हैं। दिल्ली सरकार और बिजली कंपनियां इन प्रीपेड मीटर की होम डिलीवरी करेंगी। इस सुविधा के लिए फीस भी देनी होगी, जिसमें 3000 रूपये सिक्योरिटी और 3,000 रूपये लाइन का खर्च शामिल है। सरकार ने दिल्ली में रह रहे आम आदमी को बिजली का तोहफा दिया है। 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल कर रहे लोगों को बिजली के बिल का भुगतान नहीं करना होगा। उन्हे पूरी सब्सिडी मिलेगी, इसके अलावा 201 से 401 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल कर रहे लोगों को बिल की 50 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी। पहले 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों को 622 रूपये का भुगतान करना पड़ता था लेकिन इस स्कीम के बाद उनके लिए बिजली फ्री हो जाएगी। वहीं 250 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों को 800 रूपये देने होते थे। अब नए एलान के बाद यह राशि घटकर 252 रूपये रह जाएगी। लेकिन यह फायदा सिर्फ मकान मालिक को ही मिल पा रहा था और किराएदार इससे वंचित थे लेकिन दिल्ली सरकार इस योजना के साथ इस सस्ती बिजली का फायदा किराएदारों तक पहुंचा रही है। दिल्ली में दो किलोवाट के मीटर वाले 37 लाख घरेलू उपभोक्ता और दो से पांच किलोवाट के मीटर वाले सात लाख घरेलू उपभोक्ता हैं। जबकि कुल बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 60 लाख है। घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं में 1,200 यूनिट प्रतिमाह से अधिक व्यय करने वालों के लिए बिजली की दर मौजूदा पौने आठ रुपये से बढ़ाकर आठ रुपये प्रति यूनिट कर दी गयी है। दिल्ली में बिजली के करीब 98 प्रतिशत उपभोक्ताओं की खपत 1,200 यूनिट से कम है। ऐसे में दरें संशोधित होने का फायदा उन्हें मिलेगा। डीईआरसी के अनुसार नयी दरों के बाद घरेलू श्रेणी के ग्राहकों को बिजली बिल पर 105 रूपये से 750 रूपये तक प्रति माह बचत होगी। गैर–घरेलू श्रेणी में तीन किलो वोल्ट एंपियर से अधिक के व्यय की मौजूदा दर को आठ रूपये से बढ़ाकर साढ़े आठ रूपये प्रति यूनिट किया गया है। वहीं तीन किलो वोल्ट एंपियर से कम खपत वाले छोटे दुकानदारों के लिए एक नयी उप–श्रेणी बनायी गयी है।

ये लेख Dialogue & Development Commission of Delhi की रिपोर्ट पर आधारित है।

होगी सरकार आपके द्वार

हर घर राशन यानी डोर स्टेप डिलीवरी, दिल्ली सरकार की एक क्रांतिकारी पहल है। इसके साथ ही ऐसी 150 सेवाएं हैं जो दिल्लीवासियों को घर पर मिलती हैं। दिल्ली सरकार ने 10 सितंबर 2018 को क्रांतिकारी कदम उठा कर डोरस्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज योजना की शुरूआत की थी। शुरुआत में दिल्लीवासी केवल 40 सरकारी सेवाओं का ही लाभ घर बैठे ले रहे थे जैसे कि जाति और विवाह प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और नए वॉटर कनेक्शन के घरेलू वितरण आदि जिसमें 13 गवर्मेंट सर्विसेज, 11 ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, 4 सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, 2 राशन डिपार्टमेंट, 5 दिल्ली जल बोर्ड, 2 लेबर डिपार्टमेंट, 2 महिला और बाल विभाग और एक लॉ और जस्टिस विभाग की सर्विस शामिल थी। बाद में दिल्ली सरकार ने कई नई सेवाएं जोड़ीं और धीरे धीरे 150 से अधिक सेवाएं इस योजना में शामिल कर दी गई। इसकी अवधि अगस्त, 2021 में समाप्त होने जा रही थी। दिल्ली सरकार फिर से इस योजना को और भी बेहतर तरीके से शुरू करने जा रही है और इस योजना का दोबारा से टेंडर दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि 1076 को टोल फ्री किया जाएगा। साथ ही इसे दो हिस्सों में बांट कर दो कंपनियों के माध्यम से पूरी दिल्ली में सेवाएं दी जाएंगी, ताकि उनके बीच अच्छी सर्विस देने को लेकर प्रतियोगिता भी बनी रहेगी।

अगर कोई व्यक्ति 1076 नंबर पर फोन करता है, तो दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि उनके घर पर आकर उसका काम कर के जाते हैं। इस सर्विस को एक नए तरीके से और ज्यादा अच्छा और बेहतर बनाकर दोबारा टेंडर निकाला जाएगा।

दिल्ली सरकार ने सेवाओं को फेसलेस करने पर ज़ोर दे रही है। इसके बाद

दिल्ली की जनता घर बैठे ही किसी भी सरकारी सेवा का उपयोग कर पाएगी और उन्हें सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। सभी सरकारी सेवाएं ऑनलाइन होने के बाद, दिल्लीवासियों को सिर्फ अपने कंप्यूटर में ऑनलाइन होना होगा और सभी काम सरकारी पोर्टल के माध्यम से करवा सकेंगे।

इन सरकारी सेवाओं की सुविधा पाने के लिए आपको घर बैठे 1076 नंबर पर कॉल करने के साथ एक अपॉइंटमेंट लेना होगा। अपॉइंटमेंट के बाद तय समय पर एक असिस्टेंट आपके घर आकर फॉर्म भरने, फीस जमा करने और जरूरी दस्तावेजों को जमा करके उन्हें आगे की कार्यवाही के लिए भेज देगा। जब आपके तमाम कागजात संबंधित सरकारी कार्यालय में जमा हो जाएंगे, तो उन पर आगे की कार्रवाई की जिम्मेदारी भी असिस्टेंट की होगी।

नई डोरस्टेप डिलीवरी व्यवस्था के तहत सार्वजनिक सेवाओं को अंतिम जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार मोबाइल सहायकों को आधुनिक तकनीकी के साथ ऐप की सुविधा दी जाएगी। इसमें कई अन्य सुविधाएं भी हैं, जो मोबाइल सहायकों को लोगों तक सेवाओं को पहुंचाने में मददगार साबित होंगी। मोबाइल सहायकों को यह सेवाएं घर तक पहुंचाने के बदले लोगों को पचास रुपए का मामूली शुल्क देना होगा। कोई भी व्यक्ति जो किसी कारणवश डिजिटल सेवाओं का उपयोग नहीं कर सकता है, उसके लिए डोरस्टेप डिलीवरी का विकल्प हमेशा उपलब्ध रहेगा।

कोरोना की पहली लहर में ही एक हजार दुकानों पर दिल्ली सरकार ने प्रति व्यक्ति 7.5 किलो राशन बांटने का कार्य शुरू किया और इसके साथ अन्य सरकारी राशन की दुकानों पर भी गेहूं

व चावल वितरण शुरू किया गया था। इससे दिल्ली के करीब 71 लाख लोगों को लाभ पहुंचा। दिल्ली के 568 स्कूलों और 238 रैन बसेरों में खाना खिलाने की व्यवस्था की गई। साथ ही कुछ टीमों ने भी जगह–जगह जाकर खाने के पैकेटों को बांटा।

कोरोना काल ने समाज के हर वर्ग के सामने चुनौती रखी है, और जो वर्ग इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ

आश्रय सुधार बोर्ड के मदद से सभी 223 रैन बसेरों को दिल्ली में प्रभावित लोगों को भोजन और आश्रय देने के लिए तत्काल खोल दिया। इसके अलावा, सरकार ने पूरी दिल्ली में प्रवासी श्रमिकों के लिए अस्थायी आश्रयों के साथ 1500 से अधिक हंगर राहत केंद्र भी शुरू किए।

इसके अलावा दिल्ली में रहने वाले बेघर जरूरतमंद लोगों को सभी रैन बसेरों

वो था मजदूर वर्ग। जो मजदूर अपने घर से दूर आजीविका की तलाश में प्रदेश में थे, उन्हें खाने तक की आफत आ गई। दिल्ली सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन के तुरंत बाद इससे प्रभावित होकर बेरोजगार और बेघर हुए लोगों के लिए राहत उपायों की घोषणा की। सरकार ने दिल्ली शहरी

में अब हमेशा दो वक्त का खाना फ्री मिलेगा। यह कदम मुख्यमंत्री पोषाहार योजना की शुरूआत के तहत लिया गया। दिल्ली में 209 रैन बसेरे चल रहे हैं। इन 209 रैन बसेरों में इस वक्त 6000 लोग रह रहे हैं और वो जाड़े के दिनों में बढ़कर 12000 हो जाते हैं।

चलो मुसाफिर

बेहतर रास्ते, बेहतर जिंदगी

सुगम यातायात लोगों के जीवन को सरल बनाता है। दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) देश का पहला परिवहन निगम है जिसने सीएनजी बसों को शामिल किया है। बढ़ते प्रदूषण को रोकने और सेहतमंद जिंदगी के लिए साफ हवा पाने के लिए ऐसा प्रयास मील का पत्थर साबित होगा।

दिल्ली सरकार की 'दिल्ली ईवी फोरम' की स्थापना 2020 में डीटीसी की तरफ से की गई, जिससे दिल्ली इलैक्ट्रॉनिक वाहन पॉलिसी को सफलता मिले। इस पॉलिसी के तहत 2024 तक दिल्ली की सड़कों पर 25 फीसदी इलेक्ट्रिक वाहनों को उतारने का लक्ष्य रखा गया है। इस पॉलिसी के तहत आने वाले दिनों में 5000 इलेक्ट्रिक ऑटो और 300 इलेक्ट्रिक बसें शुरू की जाएंगी।

इसके साथ दिल्ली सरकार ने दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की

इलैक्ट्रॉनिक वाहनों पर ज़ोर

जमीन इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों और बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) के साथ समझौता किया। सीईएसएल तुरंत काम शुरू करेगा और अगले 4 महीनों में सभी स्टेशनों की स्थापना को पूरा करने का प्रयास करेगा। डीटीसी और ईईएसएल के मूल्यांकन सर्वेक्षण के बाद, द्वारका सेक्टर–8, द्वारका सेक्टर 2 डिपो, महरौली टर्मिनल, ओखला सीडब्ल्यू– II, सुखदेव विहार डिपो और कालकाजी डिपो पर सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन किसे और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन स्थापित किये जा रहे हैं और नेहरू प्लेस टर्मिनल पर इसकी शुरुआत भी हो गई है। इन 7 स्थानों में से प्रत्येक में कुल 6 चार्जिंग पॉइंट होंगे, जिनमें तीन दुपहिया एवं तिपहिया वाहनों के लिए होंगे और 3 अन्य पॉइंट चार पहिया वाहनों के लिए होंगे। एक बार इनस्टॉल होने के बाद ये लोकेशन अपनी रियल टाइम लोकेशन और चार्जिंग पॉइंट की उपलब्धता के साथ दिल्ली सरकार के वन दिल्ली ऐप पर भी होंगी। इसके चलते सीईएसएल कार्बन फुटप्रिंट को भी कम करेगा और जहां भी संभव होगा, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के साथ सोलर रूफटॉप और बैटरी स्टोरेज सिस्टम (बीएसएस) को स्टोर करेगा, ताकि चार्जिंग स्टेशनों को बिजली देने के लिए रिन्यूएबल ऊर्जा का उपयोग किया जा सके।

दिल्ली सरकार ने स्विच दिल्ली अभियान की शुरुआत भी की है। जिसके तहत इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर सरकार सब्सिडी देगी। वहीं दिल्ली सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त सभी संस्थाओं में

इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाया जाना अनिवार्य बनाया है। इसके साथ ही 31 अप्रैल 2021 तक दिल्ली में 85 इलेक्ट्रिक व्हीकल सेंटर स्थापित किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक परिवहन सुविधा को बेहतर किया है। जिससे डीटीसी के बेड़े में अभी 6750 बसें शामिल है और जल्द ही 1300 नई बसों को डीटीसी में शामिल किया जाएगा।

दिल्ली सरकार विश्व स्तरीय बस डिपो हरि नगर और वसंत विहार डिपो में विकसित करेगी। यहां दिल्ली की पहली मल्टी लेवल बस पार्किंग होगी जिसमें रिटेल के साथ–साथ पार्किंग क्षमता भी 2 से 3 गुना ज्यादा होगी। इन डिपो के डिजाइन में शोर और कंपन कम करने के लिए स्टील हेलीकल स्प्रिंग्स के जरिये वाइब्रेशन आइसोलेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही पार्किंग दक्षता के लिए 45 डिग्री कोण टेक्निक का इस्तेमाल भी किया गया है। ये डिजाइन विदेशों की परियोजनाओं की केस स्टडीज के बाद किए गए हैं। इसके साथ ही 45 डिग्री कोणों का इस्तेमाल करके डिपो में 10–15 फीसदी अधिक बसें खड़ी की जा सकेंगी।

डिपो में विभिन्न सुविधाओं जैसे वाशिंग पिट, ईंधन भरने वाले स्टेशन जिन्हें भविष्य में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों में बदला जायेगा, इनको भी शामिल किया जाएगा।

डीटीसी की मौजूदा 3697 बसों में आईपी सीसीटीवी कैमरा सिस्टम, पैनिक बटन और एवीटीएस आदि लगाया गया। इसके आईटी विभाग के माध्यम से 155 व्यक्तियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

इसके अलावा दिल्ली सरकार ने आरटीओ ऑफिसों पर ताला लगा दिया, जिससे लोगों को लम्बी–लम्बी कतार और असुविधाओं से छुटकारा मिला। अब लोग घर बैठे ही ऑनलाइन सारे काम कर लेते हैं। एक निजी अखबार के मुताबिक दिल्ली परिवहन विभाग के पास 77,421 ऑनलाइन आवेदन आये, जो कि ड्राइविंग लाइसेंस और व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए थे, उनमें से विभाग ने 64 फीसदी आवेदनों को निपटा दिया। फिलहाल 12 सर्विसेज ऑनलाइन आई हैं बाकी 58 सर्विसेज बहुत जल्द ऑनलाइन आएंगी।

इसके अलावा वायु प्रदषण को खत्म करने के लिए ऑड–ईवन योजना की शुरुआत की। दिल्ली की सरकार ने महिलाओं और स्टूडेंट्स के लिए कई कदम उठाए। स्टूडेंट्स को बस पास की अनुमति है। महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए डीटीसी बसों में होमगार्ड और सिविल डिफेन्स को तैनात किया।

इसके अलावा बस में महिलाओं के लिए 25% सीटें रिजर्व किया। महिलाओं के लिए यात्रा मुफ्त कर दी गई।

दिल्ली मेट्रो पर दिल्ली की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा निर्भर करता है और डीएमआरसी इसका निर्वहन भी सही ढंग से करती है। राजधानी का हर एक कोना दिल्ली मेट्रो की लाइन से जुड़ा हुआ है। हाल में ही दिल्ली मेट्रो की ग्रे लाइन कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ जिसका नजफगढ़ से ढांसा बस स्टैंड तक विस्तार किया गया। ढांसा बस स्टैंड मेट्रो स्टेशन के खुलने से दिल्ली से बाहर के लाखों लोगों को दिल्ली आने में सहूलियत मिलेगी। करीब 50 गांवों के लोगों को दिल्ली आने के लिए अब किसी भी समस्या का सामना नहीं करना होगा। इसके साथ पिंक लाइन के त्रिलोकपुरी–मयूर विहार पाकेट वन के बीच मेट्रो परिचालन को हरी झंडी दिखाई। पिंक लाइन से अब दिल्ली के कई इलाकों उत्तर और पूर्व से लेकर दिल्ली के दक्षिण और पश्चिमी हिस्सों तक बिना रुके कनेक्टिविटी मिल सकेगी।

दिल्ली सरकार का विंटर एक्शन प्लान 10 प्रमुख बिन्दुओं पर आधारित रहेगा – जिसमें पराली और कूड़ा जलाने, वाहन व धूल प्रदूषण, हॉटस्पॉट, स्मॉग टावर, पड़ोसी राज्यों से संवाद, वाररूम और ग्रीन एप को उन्नत बनाने और केंद्र सरकार व केंद्रीय कमीशन से संपर्क शामिल होगा। इस तरह दिल्ली की ट्रांसपोर्ट सेवाएं लोगों को एक आसान और आरामदायक सफर तय करवाने के लिए तत्पर है।

देशभक्ति करिकुलम लागू

स्कूलों में पारंपरिक तौर पर हिंदी, अंग्रेजी और विज्ञान की पढ़ाई तो होती है। आज के दौर में फिजिकल एजुकेशन, फाइन आर्ट्स जैसे विषय भी शामिल किए गए हैं। ऐसे प्रयोग समय– समय पर किए जाते हैं। दिल्ली सरकार की शिक्षा को लेकर जागरूकता तो दुनिया भर में चर्चा का विषय है। अब इस शिक्षा पद्वति में देशभक्ति का भी समावेश हो गया है। यह एक नया प्रयोग है। विश्व के सभी विकसित देश खूब सारे प्रयोग करते हैं और इन प्रयोगों से कई नए विकल्प और विचार सामने आते हैं।

बात यहां दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नये पाठ्यक्रम की जा रही है, जिसको देशभक्ति करिकुलम का नाम दिया गया है। यह पाठ्यक्रम अनूठा है और इसके द्वारा फिर से दिल्ली की सरकार ने शिक्षा प्रणाली में नए प्रयोग किए हैं।

शहीद ए आजम भगत सिंह के जन्मदिन पर यानी 28 सितम्बर को देशभक्ति करिकुलम दिल्ली में लांच कर दिया गया है। इस करिकुलम में नर्सरी से 8वीं तक के बच्चों के लिए रोज़ाना और 9वीं से 12वीं तक के लिए सप्ताह में दो बार 45 मिनट की क्लास रखी गई है।

स्कूल बच्चों की पहली सीढ़ी होती है, जहां पर वो सबसे अधिक वक्त बिताते हैं। बच्चों को स्कूलों में अगर देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ाया जायेगा तो उनको देशभक्ति के सही मायने समझ में आएंगे।

इस पाठ्यक्रम को अपनाने के पीछे बच्चों को उनकी देश के प्रति जिम्मेदारी का एहसास कराना है। देश के प्रति प्रेम और सम्मान एक नैतिक मूल्य है, जिसे बच्चों में विकसित करना जरुरी है। बच्चों को उनके देश के लिए गर्व महसूस कराना यह अब स्कूलों की जिम्मेदारी होगी।

इस पाठ्यक्रम में रटने वाले कोर्स नहीं आएंगे। यह पाठ्यक्रम गतिविधियों पर आधारित होंगे। यहां पर बच्चों को देश की गौरव गाथाएं सुनाई जायेंगी। बच्चों को देश के प्रति उनके कर्तव्यों को बताया जायेगा और देश के विकास में उनके योगदान को कैसे उपयोग में लाना है, ये भी सिखाया जाएगा।

- ☛ **छात्रों में अपने देश के प्रति गर्व की भावना पैदा करना।**
- ☛ **देश के प्रति जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक करना।**
- ☛ **देश के लिए बलिदान देने की प्रतिबद्धता।**

इस करिकुलम का उद्देश्य एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जिसमे हर बच्चे के अन्दर देश की खातिर मर मिटने के लिए अपना तन, मन और धन जरूरत पड़ने पर कुर्बान कर देना है।

यह पाठ्यक्रम भारत में पहली बार दिल्ली में शुरू किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देशभक्ति पाठ्यक्रम को हरी झंडी दिखा कर ये कहा कि पिछले 70 सालों में सारे विषय पढ़ाए, लेकिन देशभक्ति नहीं पढ़ाई गई। अब दिल्ली के स्कूलों में देशभक्ति की पढ़ाई होगी। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि हम 'देश प्रेम' के मूल्यों को दैनिक जीवन के साथ जोड़ना चाहते हैं, यही देशभक्ति पाठ्यक्रम का सार है। दो साल पहले इस पाठ्यक्रम को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था, और इसमें समय के साथ सुधार करते हुए अब इसे मुख्य रूप से शुरू किया। जब मुख्यमंत्री ने 2019 में 73वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर इस करिकुलम के विजन को साझा किया था तो उन्होंने यह तीन लक्ष्य बताए थे।

देशभक्ति करिकुलम के लिए एक कमिटी बनाई गयी थी, जिसने पिछले दो सालों में टीचर्स, स्टूडेंट्स, पैरेंट्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ चर्चा और परामर्श के बाद

करिकुलम की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसे 6 अगस्त 2021 को स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च और ट्रेनिंग (एससीईआरटी) की गवर्निंग काउंसिल में मंजूरी दी गई।

देशभक्ति करिकुलम के तीन थीम हैं – पहला नॉलेज जिसमें संवैधानिक मूल्यों, देश की अखंडता और विविधता, स्वतंत्रता संग्राम, देश की उपलब्धियां, सामाजिक समस्याओं आदि का ज्ञान है। दूसरा वैल्यू जिसमें ईमानदारी, अखंडता, नम्रता, सहानुभूति, देश के प्रति प्रेम और सम्मान, करुणा, बलिदान, आदि और तीसरा जिसमें व्यवहार– अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, साइंटिफिक माइंडसेट एंड रीजिनिंग, नागरिक के रूप में जिम्मेदारियां आदि का ज्ञान है। इस पाठ्यक्रम को टीचर और स्टूडेंट्स के बीच क्लासरूम डिस्कशन, स्टूडेंट्स के बीच डिस्कशन, क्लासरूम एक्टिविटी के रूप में ग्रुप वर्क, परिवार और सोसाइटी के साथ जुड़ने के लिए होमवर्क और स्वःचिंतन (सेल्फ–रिफ्लेक्शन) जैसे 5 बाल–केन्द्रित और क्रिटिकल पैडागोजिकल प्रोसेस द्वारा पढ़ाया जाएगा। इसके साथ इस करिकुलम के माध्यम से 8 लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने की कोशिश की जाएगी जिसमें सेल्फ–अवेयरनेस, सेल्फ–कॉन्फिडेंस, प्रोब्लम सोल्विंग, संवैधानिक मूल्यों की समझ, बहुलवाद और विविधता, पर्यावरणीय स्थिरता, नैतिक सामाजिक व्यवहार, सहयोग और सामाजिक व नागरिक जिम्मेदारी शामिल हैं। अब बात मूल्यांकन कि तो विद्यार्थियों के द्वारा उनका स्व–मूल्यांकन (सेल्फ–अस्सेस्मेंट), सहकर्मी मूल्यांकन (पीयर–अस्सेस्मेंट) और टीचर्स द्वारा मूल्यांकन के तरीकों को अपनाया जाएगा।

दिल्ली सरकार के इस प्रयोग को देखना रोचक होगा और सफलता मिली तो बहुत ही लाभकारी भी क्योंकि बच्चे कल का भविष्य हैं, देश की डोर कल उनके हाथों में आने वाली है और अगर उनमें देशभक्ति के सही मायने समाहित रहे तो वह दिन दूर नहीं जब हमारा देश शीर्ष पर होगा।

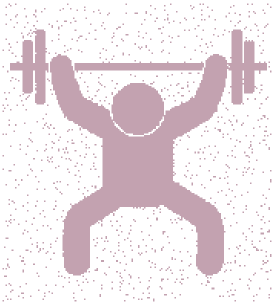

पढ़ाई खेलों की

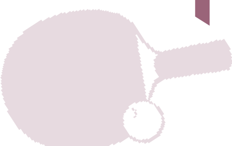

खेलों के कोर्स
निशानेबाजी
तीरंदाजी
वेटलिफ्टिंग
फुटबॉल
बैडमिंटन
क्रिकेट
टेबल टेनिस
हॉकी
एथलेटिक्स
तैराकी

खूब खेलेगी दिल्ली

बनेंगे स्पोर्ट्स स्कूल, प्लेग्राउंड और यूनिवर्सिटी

आज के दौर में सोच बदल रही है। खेलों को भी पढ़ाई जितना ही महत्व देने लगे हैं। आज का युवा खेलों में भी करियर का अवसर तलाश कर रहा हैं। पहले के समय में बड़े–बुजुर्ग यह कहते थे कि खेलोगे–कूदोगे तो होगे खराब और पढ़ोगे–लिखोगे तो बनोंगे नवाब। पर अब यह परिभाषा बदल गयी है।

जब से दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में क्रांति आई है, तब से खेलों की दुनिया में भी परिवर्तन दिखाई देने लगा है। नज़फगढ़ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी क्रांति ने जन्म लिया है। दिल्ली सरकार ने इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को हर संभव मदद मुहैया कराई है। अब आस पास के बच्चों के लिए ऐसा वातावरण विकसित किया गया है जिससे उनमें बचपन से ही खेलों को लेकर उत्साह बढ़ाया जाए और उनकी रूचि के अनुसार उन्हें ट्रेनिंग देकर तैयार किया जाए। ये कहना है नजफगढ़ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इंचार्ज राजेश कुमार का।

दिल्ली सरकार ने खेलों के महत्व को समझते हुए इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इन्हीं महत्वपूर्ण कदमों में से एक है – नजफगढ़ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का पुर्ननिर्माण। वैसे यह कॉम्प्लेक्स 1984 में बनकर तैयार हो गया था पर 2005 तक पंहुचते–पंहुचते इस कॉम्प्लेक्स की हालत खस्ता हो गयी। इसके बाद सही तरीके से रख–रखाव ना होने की वजह से जो भी बाधाएं इस कॉम्प्लेक्स को विकसित करने में आई, वो धीरे–धीरे कम होती

गयी। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक और रेसलिंग हॉल का रेनोवेशन किया गया। 2020 में एथलेटिक्स ट्रैक बनाने के लिए पैसे की मंजूरी मिल गई। बच्चों को इस कॉम्प्लेक्स में कबड्डी, रेसलिंग, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग और एथलेटिक्स जैसे खेलों की सुविधा मिलती है। इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ने कई ऐसे चेहरे दिए हैं जिन्होंने देश–विदेश में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया हैं। उन्हीं कई चेहरों में से एक चेहरा नीतिका का है, जिसने भारत का प्रतिनिधित्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो बार किया हैं। उन्होंने अंडर–15 में चाइना और अंडर–17 में रूस में रेसलिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी

इसके अलावा खेल के क्षेत्र में दिल्ली

सरकार ने एक बड़ी नींव दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की रखी। इस यूनिवर्सिटी को 2023 तक बनकर तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इस यूनिवर्सिटी का मुख्य उद्देश्य भविष्य के ओलपिंक हैं। यहां बच्चों को इस तरीके से ट्रेंड किया जायेगा जिससे उनकी प्रतिभा सही ढंग से निखर सके और भविष्य में ओलपिंक खेलों में मेडलों की बौछार हो सके। यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए 79 एकड़ जमीन आवंटित की गयी है। इस यूनिवर्सिटी में क्लास 6 से 9 तक के बच्चों का दाखिला होगा और इस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने वाले बच्चों की संख्या लगभग तीन हजार होगी। इस यूनिवर्सिटी को बनाने में लगभग 1,000 करोड़ रुपए के बजट के अनुमान लगाए जा रहे हैं। यहां पर इंडोर गेम और आउटडोर गेम ट्रेनिंग की सुविधाए भी होंगी। आउटडोर सुविधाओं में दो , दो एथलेटिक्स ट्रैक जो कि 125 मीटर प्रत्येक साइड की होगी, दो वॉलीबॉल कोर्ट, दो बास्केट बॉल और 50 मीटर शूटिंग की सुविधा। इंडोर सुविधाओं में 8–10 बैडमिंटन कोर्ट, 1 वॉलीबॉल कोर्ट और 1 बास्केटबॉल कोर्ट की सुविधाए बच्चों को दी जाएगी।

ऐसे तो दिल्ली में आई शिक्षा क्रांति को सब जानते हैं। स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के साथ स्कूलों में

वर्ल्ड क्लास स्तर के खेलों की सुविधा को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। खेलों को वर्ल्ड क्लास स्तर पर लाने के लिए दिल्ली सरकार ने 2016 में तीन सरकारी स्कूलों को स्पेशल स्पोर्ट्स स्कूल चिन्हित किया था। दिल्ली की सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूलों का निर्माण, वर्ल्ड क्लास एथलीट ट्रैक बनवाना, लॉन टेनिस कोर्ट का बनना। दिल्ली सरकार ने 2018 में पहली टेनिस अकादमी शुरू की और इसके साथ पांच नए लॉन टेनिस कोर्ट भी शुरू किये। इसके अलावा सरकारी स्कूल में वर्ल्ड क्लास हॉकी का एस्ट्रो टर्फ मैदान शुरू किया गया।

इस तरह दिल्ली सरकार ने शिक्षा में क्रांति के साथ में स्पोर्ट्स की अहमियत को समझ कर खेलों पर भी विशेष ध्यान दिया। बच्चों को खुले वातावरण में उनकी रुचि और प्रतिभा के अनुसार सरकार द्वारा सारी सुविधा उपलब्ध करवायी गई। यह सारी सुविधाएं निशुल्क होने की वजह से दिल्ली के सभी बच्चों को एक समान अवसर देने की कोशिश की गयी है। समाज के किसी भी वर्ग का बच्चा क्यों ना हो, अगर उसे खेल में रूचि हैं और उसमें प्रतिभा है तो उसे सही दिशा में ट्रेनिंग देकर एक बेहतर स्पोर्ट्सपर्सन तैयार करने में कोई बाधा नहीं आयेगी।

खेल और पढ़ाई के इस मेल को अगर देखा जाये तो यह एक बच्चे के लिए ओवरऑल डेवलपमेंट है। भविष्य की ओर देखते हुए अगर हम आगे बढ़ें तो खेल की जरूरत को समझ कर उस पर कुछ ऐसा ही विकास लाने की जरूरत है। पुरस्कार और सम्मान तो खेल का हिस्सा हैं, जो खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए जरुरी हैं, पर सबसे बड़ी पूंजी सेहतमंद स्वास्थ्य है जो खेल–कूद से ही पाया जा सकता है।

आजादी उत्सव के रंग

आजादी के 75 वें साल में दिल्ली सरकार आजादी उत्सव को उमंग और उत्साह के साथ मना रही है। हमारे देश के पास गर्व करने के लिए समृद्ध ऐतिहासिक चेतना और सांस्कृतिक विरासत का अथाह भंडार है। दिल्ली सरकार ने देश की इसी सांस्कृतिक विरासत को जन – जन तक पहुंचाने के लिए कई पहल की हैं। अमृत महोत्सव की कड़ी में दिल्ली सरकार ने देश के शहीदों को नमन करने व देश की आजादी की 75 वीं वर्षगांठ को मनाने के संदर्भ में रन फॉर दिल्ली का आयोजन किया। इसके तहत दिल्ली सचिवालय से राजघाट तक दौड़ हुई। आजादी का अमृत महोत्सव के जरिए दिल्ली सरकार देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले महान शहीदों को नमन कर रही है। देश के लिए कुर्बान हुए शहीदों का योगदान हर देशवासी के चिंतन मनन में होना चाहिए। हमारे बच्चे शहीदों के बलिदान को हमेशा याद रखें, इसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने देशभक्ति पाठ्यक्रम की शुरुआत की है। अब दिल्ली का हर बच्चा जान पाएगा कि शहीदों ने किस प्रकार अपना बहुमूल्य योगदान देकर इस भारत माता को अंग्रेजी हुकूमत के चुंगल से आजाद करवाया। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, महात्मा गांधी का विदेश से लौटना, देश को 'सत्याग्रह' की ताकत फिर याद दिलाना, लोकमान्य तिलक का "पूर्ण स्वराज्य" का आह्वान, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज का "दिल्ली मार्च",

"दिल्ली चलो" का नारा भला कौन देशवासी भूल सकता है।

इसके साथ ही दिल्ली सरकार, हर दिल्लीवासी के मन में देशभक्ति की भावना को कूट–कूट कर भरने के लिए लगातार कार्य कर रही है। दिल्ली के 500 स्थानों पर देश की आन – बान – शान हमारा प्यारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा लगाया जा रहा है। इसकी लंबाई लगभग 115 मीटर से अधिक होगी। जब भी दिल्ली के लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे, अनेक स्थानों पर लगे हमारे राष्ट्रध्वज को देखकर गदगद हो जाएंगे। दिल्ली वासियों के मन में देशभक्ति की भावना बरकरार रहेगी। ये भावना दिल्ली को आगे बढ़ाने के लिए और देश का सर्वोत्तम राज्य बनाने में कामयाब बनाएगी। अमृत महोत्सव की कड़ी में दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित रन फॉर दिल्ली कार्यक्रम में उप–मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली सचिवालय के करीब 200 कर्मचारियों को हरी झंडी दिखाकर दौड़ के लिए रवाना किया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य यह दिखाना है कि भारत की आजादी के 75 साल बाद किस तरह लोगों के दिल और आत्मा युवा हैं और ऊर्जा से भरे हुए हैं। दिल्ली के मुख्य सचिव विजय कुमार देव भी रन फॉर दिल्ली कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि दिल्ली देश के लिए उदाहरण है, जहां देश की आजादी का जश्न मनाने के लिए दौड़ का आयोजन हुआ। यह कार्यक्रम आजादी के जश्न के साथ–साथ लोगों में फिटनेस को लेकर भी जागरूकता फैलाएगा। इसके अलावा देश की आजादी के 75वें साल में दिल्ली सरकार ने 'दिल्ली सेलिब्रेट्स फ्रीडम 75' के तहत एक सीरीज शुरू

की है। इसका उद्देश्य दिल्ली को देशभक्ति के रंग में रंगना है। आजादी का अमृत महोत्सव, 15 अगस्त 2022 से 75 सप्ताह पूर्व शुरू हुआ जो 15 अगस्त 2023 तक चलेगा।

15 अगस्त, 2022 को देश की आजादी के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 75वीं वर्षगांठ

से एक साल पहले यानी 15 अगस्त 2021 से दिल्ली सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रमों को शुरुआत की गई है। ये उन लोगों को धन्यवाद देने का एक प्रयास है जिनके कारण हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। यह याद करने का समय है कि स्वतंत्रता आसानी से नहीं मिली। शहीदों ने इसे प्राप्त करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। दिल्ली सरकार शहीदों की गाथा से लोगों को रूबरू करवाने के लिए दिल्ली के अनेक स्थानों पर शहीदों के स्मारक बनवा रही है। इसी कड़ी में दिल्ली सरकार ने दिल्ली के चिराग दिल्ली में रानी लक्ष्मीबाई तथा महान क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह की भव्य मूर्तियों को स्थापित किया है। जो भी दिल्लीवासी चिराग दिल्ली के इस महत्वपूर्ण रोड से गुजरता है वो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो जाता है। वहां लगी भगत सिंह की मूर्ति देश के लिए किए गए उनके त्याग व बलिदान को आलोकित करती है। वही रानी झांसी की घोड़े पर स्थित मूर्ति उनके देश के प्रति प्यार व समर्पण को जगजाहिर करती है इसके अलावा रानी झांसी की ये दिव्य प्रतिमा दिल्ली की महिलाओं को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने शहीदों के नाम पर अनेक स्कूलों व सड़कों का नामकरण किया है।

225 झीलों का होगा कायाकल्प

सन्नोठ झील, बवाना

झीलों का शहर हो अपना

संजय वन झील, मयूर विहार

विकास पथ पर दिल्ली

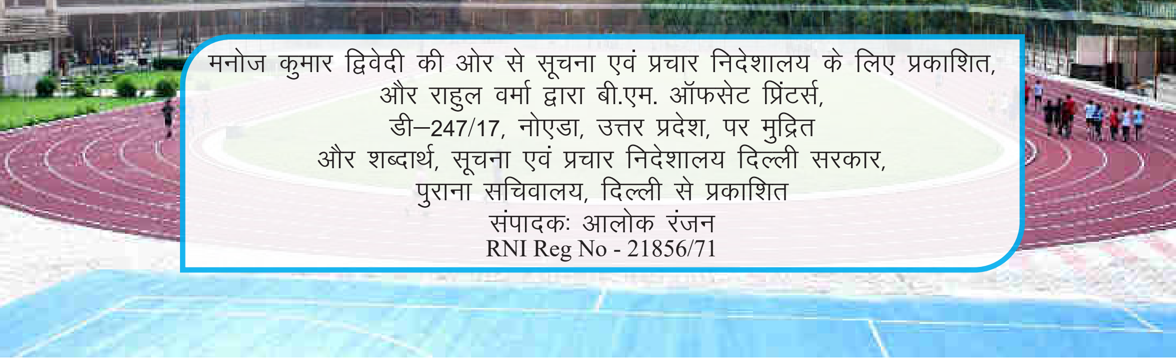

मनोज कुमार द्विवेदी की ओर से सूचना एवं प्रचार निदेशालय के लिए प्रकाशित,
और राहुल वर्मा द्वारा बी.एम. ऑफसेट प्रिंटर्स,
डी–247/17, नोएडा, उत्तर प्रदेश, पर मुद्रित
और शब्दार्थ, सूचना एवं प्रचार निदेशालय दिल्ली सरकार,
पुराना सचिवालय, दिल्ली से प्रकाशित
संपादक: आलोक रंजन
RNI Reg No - 21856/71